Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2023 GISRRJ | Volume 6 | Issue 6 | ISSN : 2582-0095

भारत में डिजिटल मनरेगा का अध्ययन

सरोज रजक
पीएच.डी. शोधार्थी (अर्थशास्त्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा, मध्य प्रदेश।

Article Info
Volume 6, Issue 6
Page Number : 144-146

Publication Issue :
November-December-2023

Article History
Accepted : 10 Dec 2023
Published : 30 Dec 2023

सारांश :– डिजिटल इंडिया एक नया अपडेट है जहाँ सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से कार्य करने के लिए उद्देश्य से शुरूआत की है। डिजिटल इंडिया मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रांड बैंक (एक दूसरो जोड़ना) का काम करना। 1 जुलाई को मान्नीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। डिजिटल योजना का कार्य साइबरस्पेस को सुरक्षित और संरक्षित बनाना, तथा डिटिजल सेवा के माध्यम से व्यवसाय को आसान तथा बेहतर बनाना। साथ ही डिजिटल सिद्धान्त का सर्वभौमिकरण बनाना। जो भी बैंक कार्य हो या सरकार का कार्य हो उसके पुराने तरीके को बंद करना तथा नये सिरे से प्रारंभ करना।

मुख्य शब्द :– ग्रामीण विकास, रोजगार, बेरोजगारी अर्थव्यवस्था, महात्मा गांधी, डिजिटल, मनरेगा।

प्रस्तावना :– भारत में डिजिटल इंडिया का मिशन हमारे मान्नीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 जून 2015 को शुरू किया गया है। हम यह नहीं कह सकते कि पहले भारत बिल्कुल भी डिजिटल नहीं था। हालांकि शहरों में ही पाया जाता था लेकिन यह मिशन ग्रामीणों तक पहुँचाने के लिए डिजिटल का विकास किया गया है। गॉव में जो लोग अपनी पहचान केवल एक मतदाता पर्ची से कराते थे उन्हें अब आधार कार्ड से पहचाना जाने लगा है तथा वर्तमान में सभी लोग आधार के माध्यम से पैसा डिजिटल रूप से निकाल सकते है । जो लोग ग्रेजुएट है वे स्मार्ट फोन के माध्यम से पैसे का लेन–देन कर सकते हैं बैंको की कतार में खड़े होने की आवश्यकता नही पड़ती है। 31 दिसम्बर 2018 तक लगभग 130 मिलियन भारतीयों को आधार कार्ड से जोड़ा गया है। यह लाखों भारतीयों के लिए प्राथमिक पहचान पत्र बन गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को वायो रासायनिक पहचान से जोड़ना कोई आसान काम नहीं था । भारत को उच्च–स्कोप इंटनेट से जोड़ने का दावा किया गया था जो कि केवल शहर तक ही सीमित था।

भारत सरकार ने उन लोगों के लिए एक डिजिटल बैंक खाता खरीदने का निर्णय लिया जिनके पास कभी भी बैंक खाता नहीं था। सरकार ने निर्णय लिया की मजदूरों की मजदूरी खाते में भेजी जाए।वर्तमान में हमारे देश में लोगों को बहुत से लाभ मिले हैं जैसे–कि ऑनलाइन सोपिंग तथा सब्जी ऑनलाइन यहॉ भी कपड़े जूते गृहस्थी का हर समान जो ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा ऑनलाइन,फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि सुविधाओं का गाँव–गाँव तक प्रचार प्रसार हो चुका है । सब्जी वाले से लेकर पान की टपरा वाले तक स्क्रेचक्यूआर कोड रखते है जिससे जनता को आसानी से पैसा भेज

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

सके। उससे फुटकर की समस्या का हल निकलता है तथा ई–स्मार्ट का भी काम तेजी चलता है। घर बैठे, लाईट का बिल, कार, का बिल आदि कोई भी सुविधा हो डिजिटल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है।

ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मनरेगा कार्डधारको को श्रम विभाग से डिजिटल कार्ड मिलेगा, इसमें सभी जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं।

मनरेगा के कार्य :–

1. जल संरक्षण एवं जल संवर्धन।
2. सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण
3. सिंचाई के लिए सुक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजना सहित नहरो कानिर्माण
4. परस्परागत जल स्रोत संरचनाओ का पुनरूद्धार (तालाबों से मिट्टी निकालने सहित)
5. बागवानी व भूमि विकास का कार्य
6. बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है।
7. हर मौसम में गांव तक पहुॅचने में रास्ते का निर्माण।
8. ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन का निर्माण।
9. इसके अतिरिक्त–राज्य सरकार की सलाह से केन्द्र सरकार द्वारा तय किया गया कोई अन्य कार्य।

मनरेगा डिजिटल मनरेगा के उद्देश्य :–

1. इस योजना का उद्देश्य उन सभी परिवारों को जो 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य कुशल शारीरिक श्रम करने के लिए अपनी इच्छा से काम करते है। उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है।
2. सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसी टिकाऊ सम्पत्तियों का विकास करना।
3. आवेदन करने पर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
4. मनरेगा योजना का सामाजिक जीवन पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन।
5. मनरेगा योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के स्वरूप में आये परिवर्तन का अध्ययन करना।
6. सामाजिक समावेशन को स्व–घोषित रूप में सुनिश्चित् करना।
7. पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त करना।
8.

मनरेगा के लक्ष्य :–

1. लक्ष्य यह है कि रोजगार अवसरो की गारंटी देकर ग्रामीण भारत में सर्वाधिक कमजोर लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
3. टिकाऊ एवं उत्पादन ग्रामीण परिसम्पत्तियों का आधार तैयार करना।

4. अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषता महिलाओं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का सशक्तिकरण।
5. विभिन्न गरीबी उन्मूलन तथा आजीविका संसाधनों के अभिमुखीकरण के माध्यम से सहभागी एवं विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।
6. पंचायतों, राज्य संस्थाओं को सुदृढ़ करके बुनियादी स्तर पर प्रजातंत्र को मजबूत करना।
7. टिकाऊ परिसम्पत्तियाँ सृजित करने वाले कार्यों के सापेक्ष मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने वाले अवसरो के माध्यम से ग्रामीण गरीबो के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना।

डिजिटल मनरेगा के लाभ :–

1. लेनदेन के लिए लोगों को बैंक जाने की जरूरत नही है ।
2. सरकारी सहायता सीधे जरूरतमंदो के खाते में आने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई।
3. जरूरतमंदो तक सहायता पहुँचाने का सरकारी खर्च घटा।
4. डिजिटल व्यवस्था में प्रवेश होने से बाजार बदल जाती है।
5. अर्थव्यवस्था में गति देने में मददगार साबित हो रहा है।
6. रोजगार के लिए आसन तरीके से आवेदन घर बैठे कर सकते है।
7. मजदूरी द्वारा न देकर बैंक में लोगो के खाते में भेज दिया जाता है।
8. मनरेगा के तहत् काम निवास से 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाता है।

संदर्भ सूची :–

1. महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर शोध अध्ययनों का संकलन 2006–2012, प्रकाशन : ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, वर्ष 2012
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, प्रतिवेदन 2 फरवरी 2013, प्रकाशन : ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार, वर्ष 2013
3. वार्षिक रिपोर्ट, प्रकाशन : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वर्ष 2022–23
4. https://nrega.nic.in/stHome.aspx
5. https://rural.nic.in/en/publications/annual-report
6. www.Jagran.com
7. www.thehindi.com
8. https://digitalindia.gov.in